EDITORIAL

ATTACKS ON PSUs and BSNL

The present Government has started attacking the Public Sector Undertakings covertly and overtly. It has so cleverly designing three pronged attacks to lessen the character of PSUs either by closures or by strategic sales or thro massive disinvestments. The attacks are routed via new ways like the recommendations of NITI Aayog, NIPFP (National Institute of Public Finance and Policy) and thro ETF mutual fund (Exchange Traded fund).

In our last Telecom, we focussed the Initiatives of NITI Aayog and its recommendations of 74 PSUs including our BSNL. We wish to bring to the attention of our employees about the other two types of attacks of the present Government on destabilizing the Public Capital and Public investment.

NIPFP is an autonomous research institute working with Ministry of Finance. It has given its recommendations by Jan 2017 about Maharatna and Mini Ratna companies. It has given its strategic map to the GOI. Maharatnas should be driven to better performance with greater autonomy and full commercialization. Private participation should be allowed more on the Coal and Defense sectors. The shocking recommendation about Air India, BSNL,MTNL- the loss making Units are outright privatisation and aggressive disinvestment. NIPFP has suggested a 10 year plan to divest at least 50 percent of the assets.

NIPFP says "The business of the government is public infrastructure, not public companies What India needs is a much-bolder plan, over the next 10 years, to divest at least half of the government share holding, largely through strategic disinvestment. How and to whom these companies are sold does matter. Russian-style privatization, where most of Russia's state assets were sold to "oligarchs", must be avoided. The opposition to such an approach will come from trade unions, vested interests and even consumers afraid of higher prices. But considering the long-term benefits to the economy and, eventually, better services and products to the consumer, this approach is worth exploring. Without such a bold approach we will perhaps see some temporary improvements in some PSU but the underlying incentives for better performance will not have changed and future generations will remain saddled with this costly socialistic legacy" One can understand from the above para how the road map is clear for the strategic sale and transfer of crores and crores of Public capital to the private hands.

The recent trend of disinvestment is 'Bunch type of Disinvestment in a single Basket' thro ETF mode. The first trail was made during 2014 after Shri Modi assumed Office. Now the Government is doing its second trail in Jan-Feb 2017. The fund is being managed by Reliance Nippon Life company. The Disinvestment target is not single PSU but bunch of PSUs like 5 or 10 PSUs and in one single basket, the shareholder will get different shares of PSUs .This is the new bonus Government is giving as attraction for popularizing disinvestments. The Bangalore convention of PSU Trade Unions has focussed this aspect as one of the serious concerns.

The Government has already ratified and given its approval for strategic sale of 20 PSUs in one cabinet sitting. The selling of even the Sick PSUs has also started. Even the core and strategic sectors are now targeted. The small PSUs like Hindustan cables, HMT watches, Thungabhadra Steels were already closed.

MTNL merger is still in the agenda. MTNL Unions are pressing the same. For an in-depth study on the implications of merger of the two PSUs, three groups have been constituted to study issues of human resources integration, technology integration and corporate integration. DOT is not denying outright the merger, but expressing its difficulties in merging the disinvested one with 100 percent Govt owned BSNL. The further losses would be on the head of BSNL.

The NITI Aayog Recommendations and the letter of PMO office are causing great concerns. The approval of Government on Tower Corporation is also hanging as Damocles' sword. The 3rd PRC is yet to come on the public light but leakage of news is there about linking wage revision with PBT (Profit Before Tax) based liability. Our PBT is negative and so the challenge is serious.

Let us take the decisions of Bangalore PSU convention to all the Employees and try our best to unite all to face the attacks. Our Calicut National Executive has guided us to rally all sections to have better Wage Revision and safeguarding the future of BSNL. Let us dedicate ourselves to these causes.

संपादकीय

बीएसएनएल सहित लोक–उपक्रमों पर प्रहार

वर्तमान केन्द्र सरकार ने लोक–उपक्रमों पर चौतरफा प्रहार शुरू कर दिया है। बड़ी चालाकी से इन्होंने लोकउपक्रम को उनके चरित्र से विमुख करने के त्रिशूल की तरह त्रिफलकीय प्रहार किया है। अब प्रहार के लिए नये रास्ते चुने गए हैं, जो नीति आयोग, राष्ट्रीय लोक नीति एवं वित्त प्रतिष्ठान, और व्यापारिक प्रवर्तन कोष (ETF) से होकर गुजरती है। पिछले माह के टेलीकाम में हमने नीति आयोग द्वारा बीएसएनएल सहित 74 लोक उपक्रमों को समाप्त करने की सिफारिश पर प्रकाश डाला था। अब हम अपने कर्मचारियों साथियों को सरकार के दो अतिरिक्त प्रहारक यूनिट के विषय में बताना चाहते हैं– जो जनता की पूंजी और निवेश को समाप्त करना चाहते हैं।

नेशनल इन्सटीयूट ऑफ पब्लिक फन्ड एन्ड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) एक स्वाधिकार प्राप्त अनुसंधान यूनिट है जो वित्त मंत्रालय के लिए काम करती है। इस ईकाई ने जनवरी 2017 में महारत्ना एवं मिनीरत्ना कम्पनियों के विषय में अपनी अनुशंसा दी है। इसने कुटनीतिक प्रारूप भारत सरकार को सौंपी है। जिसमें महारत्ना कम्पनियों को अधिक स्वाधिकृत बनाकर विशेष वाणिज्यिक बनाने की अनुशंसा है। कोयला एवं सैन्य (सुरक्षा) क्षेत्र में अधिकाधिक निजी भागीदारी देने का अनुशंसा किया है। सबसे आघातपूर्ण अनुशंसा हानि परस्त कम्पनियों यथा बीएसएनएल/एनटीएनएल को तुरत निजी हाथों में देने की सिफारिस की है। नेशनल इन्स्टीयूट ऑफ पब्लिक फन्ड एन्ड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) ने 10 वर्षों में कम से 50 प्रतिशत परिसंपत्ति की बिक्री सुनिश्चित करने की अनुशंसा की है।

एन.आई.पी.एफ.पी. कहती है कि सरकार की व्यापर जन संसाधन है लोक उपक्रम नहीं। इसका कहना है कि सरकार सख्त कदम उठाते हुए अगले दस वर्षों में सरकारी हिस्सा पूंजी का पचास प्रतिशत कुटनीतिक विनिवेश के द्वारा बेच देनी चाहिए। कम्पनी किसके हाथ बेचनी है यह सोचनीय नहीं है। रूस में जहां अधिकांश सरकारी परिसम्पदा एक ही "ओलीगर्क" को बेच दिया गया था, इस का दरकिनार करना चाहिए। श्रमिक संघ इसका विरोध करेंगे। उपभोक्ता उच्च मूल्य के कारण परेशान होंगे। पर एन.आई.पी.एफ.पी. का कहना है कि श्रमिकों का विरोध उपभोक्ता की परेशानी सबकों नजरअंदाज करते हुए इस नीति को मजबूती से बढ़ाने से दीर्घ कालिक लाभ होने की सम्भावना है। अनुशंसा के अनुसार समाजवादी परम्परा में महंगे तौर–तरीके को अगली पीढ़ी को झेलना पड़ेगा।

उपयुक्त पारा में उधृत तथ्यों से कोई भी समझ सकता है कि जनता की करोड़ों पूंजी और राष्ट्रीय जन सम्पत्ति को निजी हाथों में सौपने की रोड मैप कितनी कुटिलता से तैयार की गई है।

अभी तत्कालिक विनिवेश इ.टी.एफ. के तरीकों से करने की व्यवस्था की जा रही है जिसमें सरकार एक टोकरी में सजाकर कम्पनियों के समूह को एक साथ बिक्री करेगी। इसकी शुरूआत श्री मोदी के प्रधानमंत्री होने पर सन् 2014 में हुई। अब सरकार द्वितीय प्रयास जनवरी–फरवरी 2017 में कर रही है। कोष की व्यवस्था रिलायन्स निपोन लाइफ कम्पनी कर रही है। विनिवेश किसी एक लोक उपक्रम को एक टोकरी में सजाकर बेचने की व्यवस्था है और अंशधारकों को विभिन्न उपक्रमों में अंश प्राप्त होंगे।

सरकार ने विनिवेश को लुभावना बनाने हेतु इस प्रकार नये बोनस की व्यवस्था की है। बंगलोर में सम्पन्न समस्त लोक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी संगठनों की कन्वेंशन ने इस मुद्दे को गंभीरता से नोट किया है।

सरकार ने एक मंत्री परिषद की बैठक में बीस लोक उपक्रमों को एक साथ बेचने की अनुमति दे दी है। विमार लोक उपक्रमों की बिक्री भी शुरू हो गई है। हिन्दुस्तान केवल, एच.एम.टी. वॉचेज एवं थंगामद्रा स्टील पहले से बंद पड़े हैं।

एम.टी.एन.एल का बीएसएनएल के साथ विलय अभी भी एजेन्डे पर है। गहराई से समीक्षा के लिए तीन समिति बनाई गई है जो मानव संसाधन इन्टीग्रेशन, टेकनौजीकल इन्टीग्रेश और कार्पोरेट इन्टीग्रेशन का अध्ययन कर रहे हैं। डी.ओ.टी. विलयन से इन्कार नहीं करती है परन्तु एक विनिवेशित कम्पनी को शत–प्रतिशत सरकारी दिस्सा पूंजी से संयोजित कम्पनी का विलय में कठिनाई महसूस करती है। विलयन से आगे होने वाली हानि बीएसएनएल के सिर पर सवार होगा।

नीति आयोग की अनुशंसा एवं प्रधान मंत्री कार्यालय का पत्र एक गंभीर चिन्ता का विषय है। सहायक टावर कम्पनी बनाने के लिए सरकार की स्वीकृति भी चमकते तलवार की तरह लटक रही है। तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा प्रकाशित नहीं हुई है लेकिन कुछ चीजें बाहर आ रही है। ऐसी खबर है कि वेतन पुनरीक्षण को पी.बी.टी. (प्रोफीट बिफोर टैक्स) अधारित देयक से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। हमारा पी.बी.टी. ऋणात्मक है अतएवं यह गंभीर चुनौती भी सामने है।

हम बंगलोर में सम्पन लोक उपक्रम श्रमिक संघों की आह्वान को हर कर्मचारी तक पहुंचायें और एकताबद्ध होकर चुनौति का सामना करने को तैयार रहें। हमारे कालीकट में सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा ने निदेश दिया है कि सबको साथ लेकर अच्छे वेतन पुनरीक्षण की गारंटी के साथ बीएसएनएल कम्पनी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी।

आइये हम सभी इस पनीत कार्य के लिए अपने को संकल्पित करें।